



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357]

नई दिल्ली, बुधवार, १४ नवम्बर १९७९/कार्तिक २३, १९०१

No. 357]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 1979/KARTIKA 23, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न परी जाती है जिससे कि यह भाग संक्षेप में रूप में रूप जाए सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

प्रधिकार

नई दिल्ली, १४ नवम्बर, १९७९

सं. ३५० श्री० ६२४ (ग) -- राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा संविधान के संबंध में प्रकाशित की जा रही है :--

यह, मुझे, भारत के राष्ट्रपति नीलम संजोव रेही को मणिपुर राज्य के राज्यपाल में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और मुझे प्राप्त इस रिपोर्ट और अन्य सूचना पर विचार करते के बाव ऐसा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसके पश्चात् "संविधान" कहा गया है) के उपर्योग के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ;

अब, इस में, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं द्वारा उद्घोषणा करता हूं कि मैं --

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में लिहित या उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालता हूं ;

(ख) घोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियां संभव द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी; और

(ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध करता हूं जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या बोलतीय प्रारूप होते हैं, प्रयत् :--

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त छंड (क) के आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठोक समझूँ उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;

(ii) उस राज्य के संबंध में सविधान के निम्नलिखित उपबन्धों के प्रबंधन को एवं द्वारा विधिवत किया जाता है, प्रयत् :-- अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जिसने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निदेश करने से है ;

अनुच्छेद 151 के छंड (2) का उतना भाग जिसने का संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;

अनुच्छेद 163 और 164 ;

अनुच्छेद 166 के छंड (3) का उतना भाग जिसने का संबंध राज्य सरकार के कार्यों का भवित्वों के बीच आंतरिक से है ;

अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 169 के छंड (1) का उतना भाग जिसने का संबंध राज्य की विधानसभा द्वारा संकल्प के पारित किए जाने से है ;

अनुच्छेद 174 का छंड (1) और छंड (2) का उपबन्ध (क) ;

अनुच्छेद 175 से 178 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) ;

अनुच्छेद 179 का खंड (ख) और खंड (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक और अनुच्छेद 180 और 181 ; अनुच्छेद 186 का उनना भाग जितने का संबंध विधान-सभा के उपाध्यक्ष के संबलमों और भर्तों से है ; अनुच्छेद 188, 189, 193, 194, 195 और 196 ; अनुच्छेद 198 ; अनुच्छेद 199 का खंड (3) और खंड (4) ; अनुच्छेद 202 के खंड (3) का उनना भाग जितने का संबंध विधानसभा के उपाध्यक्ष के संबलमों और भर्तों से है ; अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें ये दोनों सम्बिलित हैं) ; अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परन्तुक और खण्ड (3) का परन्तुक ; और

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उनना भाग जितने का संबंध जापन सहित रिपोर्ट का राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;

(iii) उक्त राज्य की विधानसभा एवंद्वारा विवरित की जाती है।

(iv) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जाएगा और उसमें राज्य के विधान मंडल या उसके सदनों के प्रति निदेश का अर्थ, जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ, जब तक कि सबसे द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद के प्रति निदेश लगाया जाएगा और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल या उसके सदनों के प्रति निदेश का अर्थ, क्रमशः राष्ट्रपति और संमद या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जाएगा ;

परन्तु इसमें कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों सम्बिलित हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों सम्बिलित हैं) के उपर्यों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को इस खंड के उपर्यों (1) के प्रधीन उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी ।

(v) संविधान में राज्य के विधान मंडल के या उसके द्वारा बनाये गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निरेश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उन अधिनियमों और विधियों को जी समाविष्ट करता है और इस उद्धारण के अधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपर्यों (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं, और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) का उनना भाग जितना राज्य कि विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह उस राज्य के विधान मंडल का अधिनियम हो ।

नई दिल्ली ;

14 नवम्बर, 1979.

नीलम संजीव रेडी,

राष्ट्रपति ।

[मंधा 5/11013/3/79-सी-एस-आर०]

नई दिल्ली ;

14 नवम्बर, 1979

एम०एस०कम्पानी, सचिव

भाष्यप्रसारित

पी० पी० श्रीबास्तव, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 1979.

G.S.R. 624 (E).—The following Proclamation by the President is published for general information :—

Whereas, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, have received a report from the Governor of the State of Manipur and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely :—
  - (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;
  - (ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely :—
    - so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;
    - so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;
  - articles 163 and 164;
  - so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;
  - article 167 and so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;
  - clause (1), and sub-clause (a) of clause (2), of article 174;
  - articles 175 to 178 (both inclusive); clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article and articles 180 and 181;
  - so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 188, 189, 193, 194, 195 and 196; article 198, clauses (3) and (4) of article 199;
  - so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 208 to 211 (both inclusive); the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and
  - so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;
  - (iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved;

(iv) any reference in the Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159, (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(v) any reference in the Constitution to Acts or Laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or Laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State Laws, shall have effect in relation to any such Act or Law as if it were an Act of the Legislature of the State.

NEW DELHI; NEELAM SANJIVA REDDY,  
President.

The 14th November, 1979.

[F. No. V/11013/3/79-CSR]

NEW DELHI; M. L. KAMPANI, Additional Secy.  
The 14th November, 1979.

AUTHENTICATED

P. P. SHRIVASTAV, Jt. Secy.

प्रावेश

लां. का. नि. 625 (ग) — राष्ट्रपति द्वारा आरी किया गया निम्नांकित आदेश संवैसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आप नवम्बर, 1979 के चौहदवें दिन आरी की गई उद्योगण के खंड (ग) के उपखंड (i)

का अनुमरण करते हुए मैं एतद्वाग्न निर्देश देता हूँ कि मणिपुर राज्य नरकार के सभी कार्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्राप्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निलित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियाँ, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्योगण के खंड (क) के आवारा पर, स्वयं संभाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निवेदन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

नई दिल्ली ;

14 नवम्बर, 1979

नई दिल्ली :

14 नवम्बर, 1979.

नीलम संजीव रेडी,

राष्ट्रपति।

मामूल कम्पार्ट, अपर मचिव

अधिप्रमाणित

पी. पी. श्रीवास्तव, संयुक्त मचिव

## ORDER

G.S.R. 625(E).—The following Order by the President is published for general information:—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 14th day of November, 1979, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Manipur and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

NEW DELHI : NEELAM SANJIVA REDDY,  
President.

The 14th November, 1979.

[F. No. V/11013/3/79-CSR]

NEW DELHI;

The 14th November, 1979.

M. L. KAMPANI, Additional Secy.

AUTHENTICATED

P. P. SHRIVASTAV, Jt. Secy.

